काम पाने का मूलभूत अधिकार

2744. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए काम पाने के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार बेरोजगार लोगों को बेरोजगार भत्ता देने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : (क) और (ख) जी, नहीं, सरकार का प्रयास सीमित उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उत्पादी रोजगार अवसरों के सृजन के माध्यम से बेरोजगारी को कम करना है।

(ग) सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार यह महसूस करती है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग ऐसी योजनाओं पर किया जाना चाहिए जो उत्पादी एवं स्थायी रोजगार अवसर सृजित करें।

उत्तर प्रदेश के गांवों में जल पूर्ति योजनाओं के लिए धनराशियों का आवंटन

2745. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को विभिन्न ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिए कितनी धनराशियां आवंटित की गईं और क्या वहां धनराशियों का पूर्णतः इस्तेमाल किया गया ; और

(ख) क्या यह धन राशि उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, यदि नहीं, तो सरकार इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए उपलब्ध की गई विधियां नीचे दर्शायी गई हैं :—

धन राशि (करोड़ रुपये में)

1. छठी योजना

रिलीज	123.80
व्यय	87.15

2. सातवीं योजना

आवंटन	183.53
रिलीज	155.12
व्यय	152.52

(दिसम्बर, 1988 तक)

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत सातवीं योजना में उपर्युक्त रिलीजों के अतिरिक्त मिर्जापुर, आगरा, उन्नाव तथा सुलतानपुर के मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों (जिलों) के लिए 8.86 करोड़ रुपये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के परिव्ययों में से जल एकत्रीकरण ढांचों आदि के निर्माण के लिए 2.34 करोड़ रुपए तथा फ्लोरोसिस पर नियन्त्रण पाने तथा लौह की अधिकता को दूर करने सम्बन्धी उप-मिशनों के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के लिए लक्ष्य/कार्य योजना के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों को कवर करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि पर्याप्त थी।

खदानों में सुरक्षा संबंधी उपाय

2746. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :